



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 चैत्र 1944 (श10)
(सं0 पटना 179) पटना, रविवार, 3 अप्रील 2022

fof/k foHkx

अधिसूचना

3 अप्रील 2022

सं० एल०जी०-01-11/2022-2837/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 02 अप्रील, 2022 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

fcglj&jkT;iky dsvkn\$kl\$
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
ljdkj dsiHkjh l fpoA

[fcglj vf/fu; e 09] 2022]

fcglj jkt dksH mUjnkf; Rb , oact V izaku ½vkfu; e] 2022

fcglj jkt dksH mUjnkf; Rb , oact V izaku vf/fu; e] 2006 ½vkfu; e 5] 2006½dk l akku
djusdsfy, vf/fu; e

iLrlouk& राजकोषीय समेकन के लिए 15वें वित्त आयोग तथा भारत सरकार द्वारा यथा अनुशंसित, पुनरीक्षित रूपरेखा को लागू करने एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन प्रक्रिया को पारदर्शी तथा व्यापक बनाने के लिए राजकोषीय लक्ष्यों में संशोधन का उपबंध करने हेतु बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 में संशोधन हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1- Lf{Mr ule] foLrlj , oaijHHA &

- (1) यह अधिनियम बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2- fcglj vf/fu; e&5] 2006 dh /Hjlk&9 dk l akkuA & बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा-9 की उप धारा- 2(ख)(5) के बाद नई उप धारा-2(ख)(6) निम्नलिखित रूप से जोड़ी जायेगी :-

****2½vkfu; e] 2022-23 से 2025-26 की अवधि में राज्य के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्यों और वार्षिक उधार सीमाओं का प्रतिज्ञापन निम्नवत किया जाता है :-**

- (I) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की सामान्य निवल उधार सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत होगी।
- (II) वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 की तीन वर्ष की अवधि के लिए राज्य की सामान्य निवल उधार सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत होगी।
- (III) वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अवधि के लिए निर्धारित अधिसीमा के अतिरिक्त राज्य का वार्षिक उधार सीमा 0.5 प्रतिशत से वर्धित होगा। यह अतिरिक्त उधार सीमा भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्त के अधीन होगा।
- (IV) वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 की अवधि के दौरान किसी विशिष्ट वर्ष में राज्य अपनी स्वीकृत उधार सीमा का पूर्ण रूप से उपयोग करने में सक्षम नहीं होता है, तो उसे बाद के वर्षों में पंचाट अवधि के भीतर इस अनुपयोजित उधार राशि (जिसका रूपये में परिकलन किया गया है) का उपयोग करने का विकल्प होगा।"

**T; krlLo: i Jhokrol
ljdlj dsiHhjl fpoA**

3 अप्रैल 2022

सं० एल०जी०-01-11/2022&2838@yt—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 02 अप्रैल, 2022 को अनुमत **fcglj jkt dksH mUjnkf; Rb , oact V izaku ½vkfu; e] 2022** (बिहार अधिनियम 09, 2022) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

**fcglj&jkt; iky dsvlnsk l f
T; krlLo: i Jhokrol
ljdlj dsiHhjl fpoA**

[Bihar Act 09, 2022]
**THE BIHAR FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT
(AMENDMENT) ACT, 2022**

AN
ACT

Preamble- To amend the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006, to provide amendment in fiscal targets as recommended by the 15th Finance Commission and Government of India for application revised roadmap for fiscal consolidation and to make fiscal responsibility and budget management process more transparent and comprehensive.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventy third year of the Republic of India as follows :-

1. Short title, extent and commencement .—

- (1) This Act may be called The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2022.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint;

2. Amendment in section 9 of The Bihar Act 5, 2006.— The following new sub-section 2(b)(6) shall be added after sub-section 2(b)(5) of section 9 of the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006 (Bihar Act 5, 2006) :-

"2(b)(6) The fiscal deficit targets and annual borrowing limits for the State during the period 2022-23 to 2025-26 are enunciated as follows :-

- (I) The normal net borrowing limit for the financial year 2022-23 shall be 3.5 percent of GSDP.
- (II) The normal net borrowing limit for the three-year period of 2023-24 to 2025-26 shall be 3 percent of GSDP.
- (III) The annual borrowing limit for the period 2022-23 to 2024-25 shall be increased by additional 0.5% of GSDP. This additional borrowing space shall be subject to the condition, set forth by the Government of India.
- (IV) If the State is not able to fully utilize its sanctioned borrowing limit as specified in any particular year during the financial year 2021-22 to 2024-25, it will have the option of availing this unutilized borrowing amount (calculated in rupees) in any of the subsequent years within the 15th Finance Commission award period."

Jyoti Swaroop Srivastava,
Secretary incharge to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 179-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>